जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 16 संख्याः 269 प्रभात जालोर, बुधवार 5 जनवरी, 2022 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

एक जमाना था जब ब्रिटेन में नर कॉर्नक्रेक पक्षी की ''क्रैक्स क्रैक्स'' की तीखी आवाज रातों में लोगों को जगा देती थी खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां ये प्रजनन के लिए बसेरा करते थे, पर अब इसके प्रजनन केन्द्रों में नीरवता पसर गई है क्योंकि यह शर्मीला प्रवासी पक्षी ब्रिटेन में विलुप्ति के कगार पर है। संरक्षण के प्रयासों की बदौलत नॉर्थ वैस्ट स्कॉटलैण्ड के द्वीपों 2014 में इस प्रजाति के नर पक्षियों की आबादी 1289 हो गई थी पर उसके बाद से इनकी आबादी घटती गई और सन् 2021 में स्कॉटलैण्ड में इनकी संख्या 30 प्रतिशत तक कम होकर 850 रह गई। इन्हें बचाने के लिए स्कॉटलैण्ड में आर.एस.पी.बी. (रॉयल सोसायटी फॉर प्रोटैक्शन ऑफ बड्र्स) द्वारा ''कॉर्नक्रेक कॉलिंग प्रोजैक्ट'' चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों से कहा जा रहा है कि वे घास के मैदानों में साल के अंत में घास काटें और वो भी कॉर्नक्रेक के अनुकूल तरीके से। इंग्लैण्ड में संरक्षण केन्द्रों में इनका प्रजनन करवाया जा रहा है। इंग्लैण्ड में पेन्सथोर्पे कंजर्वेशन ट्रस्ट के संरक्षण केन्द्र में 97 कॉर्नक्रेक का जन्म हुआ इन्हें वाइल्डफाउल एण्ड वैटलैण्ड ट्रस्ट के वैलनी रिजर्व में छोड़ा गया है। पैन्सथोर्पे की क्रिसी कैली ने कहा कि ''संरक्षण केन्द्रों में जन्मे पक्षियों को खुले जंगल से अनुकूलन करने में काफी समय लगता है मुझे यकीन है कि वैलनी का ट्रायल अच्छे नतीजे देगा।'' कॉर्नक्रेक गर्मी में कॉन्गो से इंग्लैण्ड आते हैं। इनका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े हैं और मादा घास के मैदानों में ही अण्डे देती है। एक समय था पक्षी की आवाज दिन रात सुनाई देती थी लेकिन आधुनिक कृषि, जिसके लिए घास के मैदानों से समय से पहले ही मशीनों से घास काट दी जाती थी, की वजह से कॉर्नक्रेक ब्रिटेन से गायब हो गए। वैस्टर्न स्कॉटलैण्ड में इनकी कुछ आबादी है जहां कृषि के पारम्परिक तरीके से प्रयुक्त किए जाते हैं और इस वजह से इन पक्षियों को रहने के लिए लम्बी घास मिल जाती है जिनमें काफी कीड़े मकोड़े होते हैं। ब्रिटेन सन् 1993 में इनकी आबादी इतनी कम हो गई थी कि मात्र 480 नर कॉर्नक्रेक पक्षी ही बचे थे। उसके बाद इनकी आबादी बढ़ाने के प्रयास किए गए। लेकिन सन् 2014 से आबादी में निरंतर गिरावट आ रही है, जिससे संरक्षणविद चिंतित हैं। कॉर्नक्रेक कॉलिंग प्रोजैक्ट की मैनेजर जेन सैंडफोर्थ ने बताया कि अधिकांश किसान कॉर्नक्रेक के संरक्षण में सहायता करना चाहते हैं, बशर्ते सरकार उन्हें मदद दे।

क्या ओमक्रॉन का इतना अधिक व तेजी से प्रसार कोविड-19 के सिमटने के लिये शुभ समाचार है?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जनवरी। भारत और दुनिया में यहां-वहां से ओमक्रॉन केसों में हो रही वृद्धि की खबरें हमारे लिए चिंताजनक व भ्रामक, दोनों ही हैं। इस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के डेल्टा वेरिएन्ट की तुलना में ओमक्रॉन वायरस चार से पांच गुना संक्रामक पाया गया है, लेकिन इसके प्रभाव मामूली हैं, और इससे संक्रमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने की कम से कम संभावना है। तथापि, कुछ नए अध्ययनों ने ओमक्रॉन वेरिएन्ट को लेकर एक आशावाद बताया है। रिकॉर्ड संख्या में इसके पॉज़िटिव मिलने के बावजूद इसके गंभीर केस नहीं मिले हैं और लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह आंकड़े इस वैश्विक महामारी के एक कम चिंताजनक अध्याय का एक नया संकेत देते हैं।

- **गौरतलब बात यह है कि हालांकि ओमक्रॉन का प्रसार तेजी से हो रहा है, इस वायरस से संक्रमित मरीजों को कोविड-19 के संक्रमितों की भांति अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता तथा इसका प्रकोप इतना गंभीर भी नहीं है कि वैन्टिलेटर व आई.सी.यू. की जरूरत अनिवार्य हो जाये।**
- **वैज्ञानिक इस तथ्य को इस बात का संकेत मान रहे हैं कि, करोना वायरस धीरे-धीरे सिमट रहा है और इसकी जगह ओमक्रॉन ले रहा है।**

सैनफ्रांसिस्को की युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की इम्यूनोलॉजिस्ट मोनिका गांधी कहती हैं कि ''हम अब एक बिल्कुल ही भिन्न चरण में हैं।'' उन्होंने कहा कि ''यह वायरस हमेशा अपने साथ रहने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह वेरिएन्ट इतनी अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित करता है कि इससे इस वैश्विक महामारी का शमन हो जाएगा।''

साउथ अफ्रीका में एक माह पूर्व ही ओमक्रॉन वेरिएन्ट का पता चला था और विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि स्थिति बदलने में अभी भी काफी समय लगेगा, लेकिन पिछले हफ्ते से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि इस वायरस के परिणामस्वरूप व्यापक रोग प्रतिरोधता और विविध म्यूटेशन्स का मिश्रण हुआ है, जो ओमक्रॉन संक्रमण को पिछले वेरिएन्ट की तुलना में कम घातक बनाता है।

साउथ अफ्रीका में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि कोविड-19 के ओमक्रॉन वेरिएन्ट वाली चौथी लहर के दौरान जिन पॉज़िटिव रोगियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, उनमें डेल्टा वेरिएन्ट वाली तीसरी लहर के दौरान भर्ती कराए गए मरीजों की तुलना में गंभीर बीमारी होने की आशंका 73 प्रतिशत कम थी।

वैज्ञानिक कहते हैं, लगता है कि ओमक्रॉन वेरिएन्ट को कई कारकों ने कोविड-19 की पिछली लहर के मुकाबले कम संक्रामक या कम गंभीर बनाया है।

''ब्लूमबर्ग'' की एक रिपोर्ट कहती है ''कोविड संक्रमण प्राय: नाक से शुरू होता है और गले तक पहुंच जाता है। श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में हुए संक्रमण की तुलना में एक हल्का इन्फैक्शन आगे गहरायी तक नहीं पहुंचता, लेकिन जब वायरस फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तब आमतौर पर अधिक गंभीर लक्षण प्रकट होते हैं।''

लेकिन पिछले हफ्ते हुए पांच अलग-अलग अध्ययनों से पता चला कि ओमक्रॉन वेरिएन्ट पिछले वेरिएन्ट की भांति फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता। जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों के एक बड़े सहायता संघ द्वारा एडवांस में जारी किए गए एक ऑनलाइन अध्ययन में बताया गया है कि ओमक्रॉन से संक्रमित चूहा प्रजाति के हैम्सटर और चूहों के फेफड़ों में काफी कम मात्रा में नुकसान पाया गया और पिछले वेरिएन्ट्स से संक्रमितों की तुलना में इनके मरने की आशंका भी कम थी।

बेल्जियम में सीरियाई हैम्स्टर्स पर किए गए एक अन्य अध्ययन में ऐसे ही परिणाम सामने आए। सीरियाई हैम्सटर्स को इसलिए चुना गया क्योंकि वायरस के पिछले वेरिएन्ट्स में इनकी स्थिति खासतौर पर गंभीर पायी गयी थी।

हाँगकाँग में वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कुछ उन ऊतकों का अध्ययन किया, जिन्हें सर्जरी के दौरान रोगियों के सैम्पल्स के तौर पर एकत्रित किया गया था। उन्होंने पाया कि ओमक्रॉन की वृद्धि कोविड-19 के अन्य वेरिएन्ट्स के एकत्रित सैम्पल्स की तुलना में बहुत मंद थी। वायरस की प्रचण्डता में हुए इस बदलाव का संबंध शायद इससे है कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या अंता नगर पालिका के अध्यक्ष का पद कांग्रेस के हाथ से निकलेगा?

हाई कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप में नोटिस भेजा

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 4 जनवरी। राजस्थान हाई कोर्ट में जिला अंता नगर, के नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े एक अन्य पार्षद के खिलाफ, 2020 के नगर चुनाव में भाग लेने के लिए फर्जी दस्तावेज दायर करने के संदर्भ में याचिका दर्ज की गयी है।

- **अंता नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार एक वोट से जीता था। परन्तु हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष तथा कांग्रेस के टिकट पर लड़े एक अन्य पार्षद ने नामांकन पत्र में फर्जी दस्तावेज दिये हैं, ताकि वे चुनाव में भाग ले सकें।**

न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने पार्षद रामेश्वर खंडेलवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक स्वायत्त शासन तथा अंता नगर नगर पालिका के अध्यक्ष से जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में अधिवक्ता अनुराग कलावतिया पेश हुए थे। इस मामले में दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ता रामेश्वर खंडेलवाल ने कहा है कि पार्षद जमील मोहम्मद ने चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में कहा था कि उनकी पुत्री वहीदा अंसारी, का जन्म 10 अगस्त 1995 को हुआ है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उनकी पुत्री के दसवीं कक्षा के सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा है कि उनकी पुत्री का जन्म 10 अगस्त 1999 को हुआ था। याचिकाकर्ता ने अपनी दूसरी याचिका में कहा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष मुस्तफा खान ने अपने चौथे पुत्र, शाहनवाज खान, की जन्म तिथि चुनाव आयोग को 15 अगस्त 1995 बताई थी, जबकि दसवीं के सर्टिफिकेट में इनके पुत्र की जन्म तिथि 15 अगस्त 1996 वर्णित है।

याचिका में आगे बताया गया है कि राजस्थान मुनिसपैल्टी एक्ट 2009 के तहत, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार का 27 नवम्बर 1995 के बाद कोई बच्चा नहीं होना चाहिये, चाहे तारीख से पहले इस उम्मीदवार के कितने ही बच्चे पैदा क्यों न हो।

याचिकाकर्ता के वकील अनुराग कलावतिया का कहना है कि क्योंकि इन दोनों पार्षदों ने चुनाव आयोग के नॉमिनेशन पत्र में झूठी गवाही दी और अपने बच्चों की जन्म तिथि गलत बताई, उन्होंने कहा कि, इन दोनों ने नगर पालिका विधेयक 2009 की धारा (24) का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जिसके तहत वर्ष 1995 के बाद जिस व्यक्ति के बच्चे होते हैं वे नगर पालिका के सदस्य नहीं हो सकते, ''इसलिए यह दोनों नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।''

याचिकाकर्ता रामेश्वर खंडेलवाल ने याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि वे नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव में उतरे थे, परन्तु यह चुनाव मुस्तफा खान एक वोट से जीते थे। उन्होंने आगे बताया कि जमील मोहम्मद ने मुस्तफा खान के समर्थन में वोट डाला था।

याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि क्योंकि मुस्तफा खान व जमील मोहम्मद ने अपने नॉमिनेशन पत्र में झूठ बोला है इसलिये उनका चुनाव ही रद्द होना चाहिये, परन्तु अब यह स्पष्ट नहीं है कि कि नगर पालिका अध्यक्ष किसे माना जायेगा। बहरहाल अदालत ने इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख दी है।

हाईकोर्ट

जयपुर, 4 जनवरी (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने करोना के ओमक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसों को देखते हुए पांच जनवरी से 14 जनवरी तक हाईकोर्ट सहित जयपुर और जोधपुर की सभी अधीनस्थ अदालतों में प्रकरणों की सुनवाई केवल वर्चुअल तरीके से ही करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश की कॉपी जजों, न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशनों को भेजते हुए कहा है कि प्रदेश में करोना के

- **जोधपुर की अदालतों में 14 तक वी.सी. से सुनवाई होगी।**

बढ़ते मामलों के कारण वीसी के जरिए ही सुनवाई का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में 75 फीसदी कोर्ट कर्मचारी ही रोटेशन के आधार पर कोर्ट आएंगे। जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे, वहीं कोर्ट परिसर में केवल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी दो सप्ताह के लिए केसों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड से ही करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट सहित अन्य हाईकोर्टों में भी वीसी के जरिए ही सुनवाई करने के आदेश जारी हो चुके हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पिछले चौबीस घंटों में फिर दोगुने हुए करोना के नए मरीज राजस्थान में

प्रदेश में मंगलवार को 1137 नए संक्रमित मिले हैं तथा सोमवार को 550 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 4 जनवरी । प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में नए करोना संक्रमितों की संख्या फिर दोगुनी हो गई है। इसके चलते मंगलवार को 1137 नए संक्रमित सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 745 मरीज जयपुर जिले में मिले हैं। इस बीच राजधानी में करोना से एक संक्रमित की मौत भी हुई है।

- **राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 745 और जोधपुर में 185 नए संक्रमित सामने आए हैं।**
- **राज्य में करोना के एक्टिव केस तीन हजार के पार हो गए हैं। इनमें 2135 मामले जयपुर में हैं।**
- **करोना संक्रमण से जयपुर में एक मरीज की मौत भी हुई मंगलवार को।**

प्रदेश में जांचे बढ़ने के साथ ही करोना संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि होने लगी है। मंगलवार को राज्य में 53 हजार 524 जांच पर 1137 नए संक्रमित सामने आए हैं।

इससे पहले सोमवार को 550 रोगी पाए गए थे। इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा 745 नए संक्रमित जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 185, अजमेर में 43, अलवर में 39, कोटा में 31, भीलवाड़ा में 21, भरतपुर में 20, बीकानेर में 12, उदयपुर में 9, प्रतापगढ़ में 8, चित्तौड़गढ़ व गंगानगर में 7-7, सीकर, सिरोही, टोंक व बाड़मेर में 2-2 तथा दौसा और धौलपुर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

उधर राहत की बात यह है कि राज्य के 15 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर में एक भी नया केस नहीं मिला है। इस बीच प्रदेश में केवल 37 मरीज ही ठीक होने के साथ ही अब तक 9 लाख 46 हजार 422 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में लगातार नए संक्रमितों में हो रही भारी वृद्धि के कारण रिकवरी रेट गिरकर 98.73 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं संक्रमण दर 2.12 फीसदी हो गई है। इधर प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 3183 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2135 मामले जयपुर जिले में हैं।

इसके अलावा जोधपुर में 364, अजमेर में 118, कोटा में 110, अलवर में 107, बीकानेर में 57 और भीलवाड़ा में 55 तथा अन्य 15 जिलों में इससे कम एक्टिव केस मौजूद हैं। जयपुर में मंगलवार को करोना संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही राजधानी में अब तक इस बीमारी से 1972 लोगों मृत्यु हो गई है। जबकि प्रदेश में 8965 लोगों की मौत हुई है।

धरना 13वें दिन भी बदस्तुर जारी

कोटपूतली, 4 जनवरी (निसं)। कोटपूतली में मास्टर प्लान के अनुरूप कस्बे की मुख्य सड़कों को चौड़ा किये जाने को लेकर स्थानीय नगर पालिका मण्डल की कार्यवाही के विरोध में नगर

- **जिला कलैक्टर को भेजे ज्ञापन में कसाना ने दी चेतावनी। यदि मास्टर प्लान के नाम पर अवैध रूप से प्रतिष्ठान व मकानों को तोड़कर लोगों को सड़कों पर लाने का काम किया तो प्रशासन गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे।**

व्यापार महासंघ संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को लगातार 13वें दिन भी जारी रहा।

मंगलवार को राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (आर.एल.पी.) ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यपाल व राज्य सरकार में ठन रही विश्वविद्यालयों में वी.सी. की नियुक्ति पर

यह तनातनी विशेषकर उन राज्यों में है जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जनवरी। ममता बनर्जी ऐसी एकमात्र मुख्यमंत्री नहीं हैं, जो यह चाह रही है कि राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के औपचारिक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका, दायित्वों एवं अधिकारों से वंचित कर दिया जाये। महाराष्ट्र में तो ऐसा विधेयक भी पारित हो चुका है जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों से जुड़े अधिकारों में कटौती कर दी गई है। तमिलनाडु और केरल सरकार भी इसी प्रकार के कानून लाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही हैं। उच्च शिक्षा का राजनीतिकरण कहे जाने वाले मुद्दों पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के बीच अनबन चली आ रही है। इन मुद्दों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण बिन्दु रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जगदीप धनकड़ ने अभी हाल ही उनकी सहमति के बिना ही राज्य में 24 वाइस चांसलरों की नियुक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। धनकड़ ने 30 दिसम्बर को कहा, ''इन नियुक्तियों की कोई कानून-सम्मत स्वीकृति नहीं हैं तथा अगर इन्हें शीघ्र ही वापस नहीं लिया गया तो उन्हें कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।'' इस बीच, टी.एम.सी. सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है, जिसके जरिये राज्यपालों को ऐसे अधिकारों से वंचित करके ये अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिये जायें।

- **प.बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने, उदाहरण के लिये, राज्य के 24 विश्वविद्यालयों में हाल ही में हुई वी.सी. की नियुक्तियों पर आपत्ति की।**
- **केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन को पत्र लिखकर कहा कि, उनसे बहुत दबाव बनाकर कुन्नूर विश्वविद्यालय के वी.सी. की नियुक्ति करवायी गयी है। यह अनुचित है, वे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति का पद त्याग रहे हैं, तथा मु.मंत्री यह जिम्मेवारी सम्भाल लें। अन्यथा ऐसा कानून पारित करें, जिससे दुखदायी सवाल बार-बार न उठे।**
- **महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्यपाल के वी.सी. नियुक्ति के अधिकार पर अंकुश लगाते हुए, वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया में ही परिवर्तन कर दिया है। नयी प्रक्रिया के अनुसार, अब चयन समिति पांच व्यक्तियों के नाम की सूची प्रस्तुत करेगी, सरकार के समक्ष, इनमें से वी.सी. को नियुक्त करने के लिए। सरकार इस सूची को ''शार्ट-लिस्ट'' करके गवर्नर को इनमें से दो नाम भेजगी, तथा इन दोनों में से एक व्यक्ति चयन करना होगा राज्यपाल को तीस दिन के अन्दर।**

ऐसा ही एक विवाद केरल में गोपीनाथ रवीन्द्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय का वी.सी. बनाये जाने को लेकर उभरकर आया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि उन्होंने रवीन्द्रन के नाम की स्वीकृति दबाव में आकर दी थी। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन को पिछले माह लिखे एक पत्र में, खान ने यह कह दिया था कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर का पद छोड़ रहा हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि या तो उनकी जिम्मेदारियाँ अधिगृहीत कर ली जायें या फिर इस विवादास्पद प्रश्न का समाधान करने के लिये कानून लाया जाये। विश्वविद्यालय अधिनियम के जरिये, राज्य सरकारों की भूमिका अदा करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्बला मैदान

जयपुर, 4 जनवरी (निसं)। राजधानी जयपुर की वक्फ सम्पत्ति कर्बला मैदान में पिच निर्माण और टूर्नामैन्ट कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष युनुस चोपदार ने राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बिना अनुमति के कर्बला मैदान में पिच निर्माण और टूर्नामैन्ट आयोज को लेकर कहा है कि

- **एक दर्जन से ज्यादा मुस्लिम संगठन आज सुबह 11 बजे कूच करेंगे। कर्बला मैदान पर जोर जबरदस्ती से क्रिकेट मैच आयोजित करने के विरोध में।**

यहां यदि टूर्नामैन्ट होगा, तो मेरी लाश पर होगा।

जयपुर के कर्बला मैदान में जलदाय मंत्री महेश जोशी द्वारा सीमेंटेड पिच का अवैध रुप से निर्माण करवाने और वहां पर टूर्नामैन्ट आयोजित करने के मामले मे मुस्लिम संगठनों ने पांच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)